

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

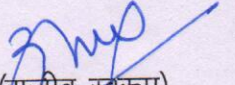
कमांक प .9(1) प्र.सु./सम/अनु.-1/2018

जयपुर, दिनांक 14.09.2020

“परिपत्र”

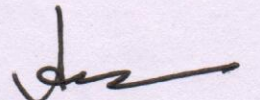
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जन घोषणा के बिन्दु संख्या 27.42 में राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राजकीय तथा जनता के कार्यों की फाईलों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण तथा जनता के प्रति जवाबदेही को निर्धारित करने के संबंध में सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम वर्ष 2011 के अंतर्गत राज्य सरकार में 25 विभागों की 221 लोक सेवाओं के लिये निर्धारित समयावधि में निस्तारण कर आमजन को इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। जिसमें कार्य का तय समय पर नहीं होने की स्थिति में अपील एवं शास्ति का प्रावधान निर्धारित किया गया था। लेकिन राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय तथा जनता के कार्य निर्धारित समय-सीमा पर सम्पादित नहीं हो रहे हैं। जिससे आम जनता को इसका लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है।

अतः अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवगणों को निर्देशित किया जाता है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की क्रियान्विति सुचारु ढंग से नहीं करने वाले दोषी अधिकारी /कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे।


(राजीव श्रीवस्तव)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त जिला कलेक्टर
6. उप शासन सचिव, जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग
7. रक्षित पत्रावली


(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव